This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 03 मई, 2023 / 13 वैशाख, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st March, 2023

No. HHC/GAZ/14-385/2018.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 05 days' commuted leave *w.e.f.* 04-07-2022 to 08-07-2022 and further 14 days'commuted leave *w.e.f.* 16-07-2022 to 29-07-2022, in favour of Ms. Swati Barwal, Civil Judge-*cum*-JMFC (I), Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of SCHEDULE-'B'.—In SCHEDULE-'B' appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 2021 (herein after to be referred as "said rules") in the heading "CO-OPERATION DEPARTMENT" appearing at Sl. No. 4, for the item No. 1, the following shall be substituted, namely:—

"All work relating to Co-operative Societies of all types and at all levels, registered under the Co-operative Societies Act, except major Co-operative Banks namely Himachal Pradesh State Co-operative Bank, Kangra Central Co-operative Bank, Jogindra Central Co-operative Bank and administration of Section 35, 94 and 100 of the Himachal Pradesh State Co-operative Societies Act, 1968 in relation of Himachal Pradesh State Co-operative Milk Producers Federation Ltd., Himachal Pradesh State Co-operative Wool Federation and their constituent Co-operative institutions."

3. In SCHEDULE-'B' appended to the 'said rules', in the heading, "FINANCE DEPARTMENT" appearing at Sl. No. 9, in sub-heading (a) for item No. 24, the following shall be substituted, namely:—

"All matters relating to banks, banking commission and major co-operative banks namely Himachal Pradesh State Co-operative Bank, Kangra Central Co-operative Bank, Jogindra Central Co-operative Bank registered under Himachal Pradesh State Co-operative Societies Act, 1968."

By order,

Pr. Secretary (GAD).

सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्रीमण्डल)

अधिसूचना

शिमला–2 01 मई, 2023

संख्याः जी.ए.डी.–सी–ए(3)2 / 2019–1.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी.ए.डी.–सी–ए(3)2 / 2019, तारीख 10 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 13 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 'अ' का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) की अनुसूची–'अ' में क्रम संख्या 7 के शीर्षक ''पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

''पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।''।

3. अनुसूची 'आ' का संशोधन.—(क) उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 'आ' में क्रम संख्या 7 के शीर्षक ''पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग'' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग'';

(ख) क्रम संख्या 7 के शीर्षक (अ) (ख) 21. में ''प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन'' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''प्राकृतिक आपदा''; और

(ग) क्रम संख्या 7 के शीर्षक (इ) ''जैव प्रौद्योगिकी'' के पश्चात् निम्नलिखित नव शीर्षक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''(ई) जलवायु परिर्वतन

1. जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास पर राष्ट्रीय लक्ष्यों, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर अवधारित योगदान (एन डी सी) और सतत् विकास विकास लक्ष्य (एस डी जी) के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर हिमाचल प्रदेश राज्य कार्य योजना (एस ए पी सी सी) की सहायता, सुदृढ़ीकरण और कार्यान्वयन।

2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए हिमाचल परिषद् में जलवायु परिवर्तन पर राज्य केन्द्र को सुदृढ़ करना और जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप सतत् और जलवायु—तन्यक (लचीला) विकास को सुनिश्चित करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए हिमालयी क्रायोस्फीयर, कृषि—बागवानी, जल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करना।

3. विभिन्न विभागों, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और क्षमता और कौशल विकास में सहायता के लिए परिवर्तन प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना।

4. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रयोजन के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विकसित करने पर मार्गदर्शन करना।

5. ज्ञान प्रबंधन, पहुंच और दृश्यता के लिए जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल का विकास और समर्थन करके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर मीडिया, युवाओं, लाइन विभागों, सिविल समाज आदि के लिए जन—जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करना।

6. साम्या और समावेशिता पर केन्द्रित कार्बन तटस्थता (नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अल्प कार्बन—गहन शहरी केन्द्रों का विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत् परिवहन नेटवर्क और प्रदूषण—नियंत्रण पर केन्द्रित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना) से संबंधित नीतिगत मुद्दों को बढ़ावा देना।

7. वन, जल, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विद्युत आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय रोडमैप विकसित करते हुए निम्न कार्बन युक्तियों और व्यवसाय मॉडल सहित जलवायु परिवर्तन पर उनकी कार्य योजना (अनुकूलन और शमन दोनों) के विकास में विभिन्न लाइन विभागों की सहायता करना और क्षेत्रीय / फ्लैगशिप योजनाओं और नीतियों में अनुकूलन और शमन पहलुओं के एकीकरण को सुनिश्चित करना।

8. राज्य में वित्तीय निर्णय लेने और बजटीय प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का उन्नत व्यवस्थित एकीकरण और जलवायु परिवर्तन विवक्षाओं पर विचार करते हुए राज्य और उप—राज्य स्तरों पर अनुकूलन योजना को सुकर बनाना।

9. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्रोतों से जलवायु कार्य के लिए वित्त संघटित करना, वित्त तक पहुंच, लाभ उठाने (प्रभाव क्षमता) और वित्त जुटाने के लिए प्रस्ताव बनाना, उदाहरण के लिए हरित जलवायु निधि, एन ए एफ सी सी।

10. जलवायु परिवर्तन हस्तक्षेपों उदाहरण के लिए अतिसंवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन कार्यकलाप योजना, निगरानी और मूल्यांकन आदि के सफल कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान अंतराल और प्राथमिकता अनुसंधान आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन करना।

11. राज्य में जलवायु परिवर्तन पर सतत् अनुसंधान और कार्यों में सहायता करना । जलवायु क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलापों का समर्थन करने और वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहकार्यता और सहयोग को मजबूत करना।

12. जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी समस्त मुद्दों के लिए भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों के साथ समन्वय करना।

13. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन ए पी सी सी) के लक्ष्यों और एस ए पी सी सी के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना।

14. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र आदि जैसे बहुहितधारकों के साथ तन्यकता बनाने में संलग्न होना।"

राज्यपाल के आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन)।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-C-A(3)2/2019-Part-I, dated 01-05-2023 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CONFIDENTIAL & CABINET)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 1st May, 2023

No. GAD-C-A(3)2/2019-Part-I.—In exercise of the powers conferred by Clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 2021 notified *vide* Notification No. GAD-C-A(3)2/2019, dated 10th December, 2021 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 13th December, 2021, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) (1st Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of SCHEDULE 'A'.—In the SCHEDULE-'A' appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 2021 (hereinafter to be referred as "said rules") for the heading at Sl. No.7 "Environment, Science and Technology Department" the following shall be substituted, namely:—

"Department of Environment, Science, Technology and Climate Change".

3. Amendment of SCHEDULE 'B'.—(a) In SCHEDULE-'B' appended to the 'said rules', for the title at Sl. No.7, "ENVIRONMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT", the following shall be substituted, namely:—

"DEPARTMENT OF ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY AND CLIMATE CHANGE";

(b) in the title, 'DEPARTMENT OF ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY AND CLIMATE CHANGE' appearing at Sl. No. 7, in heading (A) (b) (21), for the words "Natural Disaster and Climate Change", the following shall be substituted, namely:—

"Natural Disaster"; and

(c) in the title, 'DEPARTMENT OF ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY AND CLIMATE CHANGE' appearing at Sl. No. 7, after heading (C) Bio-Technology, the following new heading shall be added, namely:—

"(D) Climate Change

1. Support strengthening and implementation of Himachal Pradesh State Action Plan on Climate Change (SAPCC) aligning with National Goals on Climate Change and sustainable development such as Nationally Determined Contributions (NDCs) and Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Strengthen the State Centre on Climate Change in the Himachal Council for Science, Technology & Environment and generate strategic knowledge on Climate Change with reference to the himalayan cryosphere, agri-horti, water, and other allied sectors for informed decision making to ensure sustainable and climate resilient development in consonance with important national missions of Govt. of India on Climate Change.

3. Assess the Climate Change training needs for various departments, educational institutions, research institutions and support in capacity and skill development.

4. Provide guidance on developing various courses and curricula for educational purpose in the context of Climate Change.

5. Undertake public awareness and capacity building programme for media, youth, line departments, civil society etc. on environment and climate change issues by developing and supporting climate change knowledge portal for knowledge management, outreach and visibility.

6. Promote policy issues related to carbon neutrality (reducing emission of greenhouse gases with focus on renewable energy, energy efficiency, development of less carbon

intensive urban centres, waste management, sustainable transportation network, and pollution control) with focus on equity and inclusiveness.

7. Support various line departments in development of their Action Plan on Climate Change (both adaptation and mitigation) including low carbon strategies and business models by developing sectoral roadmaps for priority sectors such as forest, water, agriculture, health, energy, power etc. and ensure integration of adaptation and mitigation aspects in sectoral/ flagship schemes and policies.

8. Advance systematic integration of Climate Change concerns into financial decision-making and budgetary process in the State and facilitate adaptation planning at state and sub-state levels considering Climate Change implications.

9. Develop proposals for accessing, leveraging and mobilizing finance for climate action from various international and national sources of Climate finance *e.g.* Green Climate Fund, National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) etc.

10. Undertake various scientific studies pertaining to research gaps and priority research needs for successful implementation of Climate Change interventions *e.g.* vulnerability and risk assessment, climate change adaptation and mitigation activity planning, monitoring and evaluation etc.

11. Support in sustained research and actions on Climate Change in the State. Strengthen collaboration and cooperation with international and national research institutions to support research activities in the climate sector and promote an augmentation of scientific knowledge.

12. Co-ordinate with various Central Ministries-Government of India and State line departments for all the issues related to Climate Change.

13. Monitoring and evaluation of implementation of National Action Plan on Climate Change (NAPCC) targets and State Action Plan on Climate Change (SAPCC).

14. Engage with multi-stakeholders such as NGOs, bilateral and multi-lateral agencies private sector etc. for promoting Climate Change adaptation and mitigation responses for building resilience."

By Order of the Governor,

Pr. Secretary (GAD).

In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Pankaj Kumar age 32 years s/o Rakesh Kumar, r/o Village Banal, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

2. Hilo Devi aged 31 years wd/o Vijay Kumar, r/o Village Ser, P.O. Dhaned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . *Applicants.*